

अपर समाहर्ता का न्यायालय, गोड्डा
RMA No- 34/2001

34/32/2022

अपीलकर्ता-मो० समीरूद्दीन

बनाम

उत्तरवादी- मो० मजहर वगै०

-: आदेश :-

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेखबद्ध कागजातो का अवलोकन किया।

वर्तमान अपीलवाद विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में निष्पादित बंदोवस्ती केश नं०-03/2000-01 मु० मजहर वगै० बनाम् मु० समीरूद्दीन से संबंधित मामला में दिनांक-22.06.2001 को पारित आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा यह वाद श्रीमान् उपायुक्त महोदय गोड्डा के न्यायालय में दायर किया गया है जिसे दिनांक-09.06.2004 को हस्तांतरण के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातो एवं निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता है कथन है कि वर्तमान प्रक्रिया चलने योग्य नहीं है क्योंकि संधाल परगना कारशाकारी पूरक अधिनियम-1949 के तहत कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्वयं की गयी बंदोवस्ती को रद्द या संशोधन करे। परन्तु विषयगत बंदोवस्ती अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की गयी है और बन्दोवस्ती केनसिलेशन के लिए विपक्षी को उच्चतर न्यायालय में अपील दायर करना चाहिए था जबकि विपक्षी बंदोवस्ती के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं किया अपितु पुनः अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर किये जो नियमविरुद्ध है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। जिसे रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

वही विपक्षी की ओर से सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने आदेश में मौजा-ब्रम्हपुर उर्फ जहाजकित्ता के दाग नं०-28 के रकवा- 00-01-18 धूर जमीन के अन्दर उत्तर तरफ 15 फीट चौड़ा रास्ता आम जनो के आवागमन के लिए छोड़ा गया है। किसी का रास्ता अवरुद्ध करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय में पारित आदेश युक्ति संगत है अतः वर्तमान अपील स्वीकार्य योग्य नहीं है इसे खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस को सुना तथा अभिलेखबद्ध दस्तावेज का अवलोकन एवं बहस सुनने के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अंचल अधिकारी, पथरगामा ने स्थल जाँच प्रतिवेदन के उपरांत प्रतिवेदित किया है कि मौजा-ब्रम्हपुर उर्फ जहाजकित्ता के दाग नं०-28 के कुल रकवा- 01-00-00 धूर गत सर्वे सेटलमेंट में परती कदीम करकर दर्ज है। इसी जमीन से सटे आवेदक का मकान है तथा प्रस्तावित (बंदोवस्त जमीन) रकवा 00-01-18 धूर जमीन पर आवेदक का सहन आवास के सामने विषयगत भूमि का उपयोग आंगन के रूप में किया जा रहा है।

विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय का बंदोवस्ती केश नं०-128/1994-95 मो० समीरूद्दीन बनाम् रैयान मौजा-ब्रम्हपुर उर्फ जहाजकित्ता से संबंधित केश में अंचल अधिकारी, पथरगामा ने स्थल जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होने के उपरांत मौजा-ब्रम्हपुर उर्फ जहाजकित्ता के दाग नं०-28 के कुल रकवा-

01-00-00 धूर के अन्तर्गत 00-01-18 धूर भूमि का उपयोग आंगन के रूप में किये जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत भूमि आवेदक मो० समीरुद्दीन, पे०-शेख कोकू के साथ मौजा- जहाजकित्ता, दाग नं०-28 के अंश रकवा 00-01-18 धूर भूमि बंदोवस्ती की स्वीकृति बंदोवस्ती केस नं०-128/1994-95 के द्वारा प्रदान की गयी। चूंकि इस वाद में पूर्व के आदेश दिनांक-31.01.2012 में स्पष्ट किया गया है कि जब विषयगत वाद अंचल अधिकारी, पथरगामा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। फलस्वरूप पुनः अंचल अधिकारी, पथरगामा से जाँच करवाना उचित नहीं है।

अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केस नं०-128/1994-95 मो० समीरुद्दीन बनाम् रैयान मौजा-ब्रम्हमपुर उर्फ जहाजकित्ता में पारित आदेश के आलोक में विपक्षी को उच्चतर सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था परन्तु विपक्षी ने ऐसा नहीं किया गया। जबकि पूर्व में एक ही संपत्ति/भूमि के बाबत एक ही पक्षकारों के मध्य एक ही न्यायालय में विवाद का निस्तारण कर वाद का अंतिम निर्णय कर अंतिम आदेश पारित किया गया। लेकिन पुनः उसी संपत्ति/भूमि के बाबत उन्ही पक्षकारों के मध्य पुनः रास्ता को लेकर उत्पन्न विवाद के फलस्वरूप पुनः अनुमंडल पदाधिकारी के ही न्यायालय में वाद दायर किया गया। इस प्रकार पुनः उक्त वाद में पारित किया गया आदेश दूसरे वाद में पक्षकारों के मध्य पारित आदेश Code of Civil Procedure 1908 Res-Judicata के तहत बाध्यकारी होगा। इस प्रकार पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, के न्यायालय में बंदोवस्ती केस नं०-03/2000-01 (मु० मजहर वगै० बनाम् मु० समीरुद्दीन) दायर किया गया जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1980 की धारा-11 पूर्व-न्याय (Res Judicate) के प्रतिकूल है।

इसप्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय का बंदोवस्ती केस नं०-03/2000-01 (मु० मजहर वगै० बनाम् मु० समीरुद्दीन) नियमसंगत नहीं है। अतः उक्त वाद में दिनांक-22.06.2001 को पारित आदेश खारिज किया जाता है। असंतुष्ट पक्षकार सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता,
गोड्डा।

अपर समाहर्ता,
गोड्डा।